माननीय न्यायमूर्ति पी. सी. जैन, सी. जे. और एस. एस. कांग के समक्ष

कृष्ण लाल और अन्य, - याचिकाकर्ता,

बनाम

टेक चंद और अन्य, - उत्तरदाता।

सिविल संशोधन सं. 1985 का 2668

29 जुलाई, 1986।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V) - *आदेश* 1, *नियम* 10 - विशिष्ट *राहत अधिनियम* (1983 *का XLVII*) - *धारा* 19 - विक्रेता के *खिलाफ विक्रेता द्वारा दायर बिक्री के लिए एक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा - विक्रेता के साथ संयुक्त मालिक होने का दावा करने वाला एक अन्य व्यक्ति* जो हमें *पक्षकार* बनाने की मांग करते हुए आवेदन दायर करता है*।प्रतिवादी - आवेदक बेचने के लिए समझौते का एक पक्ष नहीं - ऐसा आवेदक - चाहे एक आवश्यक या उचित पार्टी होने के नाते प्रतिवादी के रूप में शामिल होने का हकदार हो।*

यह अभिनिर्णित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 के नियम 10 के उप नियम (2) के प्रावधान न्यायालय को यह निर्देश देने का अधिकार देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था या जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि अदालत को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने और मुकदमे में शामिल सभी सवालों को निपटाने में सक्षम बनाया जा सके। बिक्री के लिए एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक साधारण मुकदमे में, निष्पादकों के बीच किए गए अनुबंध को लागू करने के उद्देश्य से प्रतिवादी के खिलाफ मांगी गई डिक्री, बिक्री के लिए समझौते के लिए अजनबियों के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी जाती है और वास्तव में, ऐसे मुकदमे में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राहत का कोई अधिकार नहीं है जो समझौते का पक्ष नहीं है। ऐसे मामले में, वादी विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री प्राप्त करने की स्थिति में, एक बिक्री विलेख निष्पादित करेगा जो केवल उसके निष्पादकों को बाध्य करेगा और उन व्यक्तियों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा जो समझौते के पक्षकार नहीं हैं। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 19 में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी संविदा का विशिष्ट निष्पादन उसके किसी भी पक्ष के विरुद्ध लागू किया जा सकता है। इसलिए, इस तरह के मुकदमे में एक व्यक्ति जो बिक्री के लिए समझौते का पक्ष नहीं है, न तो आवश्यक है और न ही उचित पार्टी है। यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि वादी एक मुकदमे में डोमिनस लिटस है और ऐसे वादी को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिसके खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि मुकदमे में शामिल सवालों को निपटाने के लिए ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक होनी चाहिए। इन सवालों को निपटाने के लिए अजनबियों की उपस्थिति जो अनुबंध के पक्षकार नहीं हैं, आवश्यक या उचित नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब तक जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित किसी पार्टी का विवाद और उसके अधिनिर्णय में प्रत्यक्ष हित नहीं है, तब तक आदेश 1 के नियम 10 के उप नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में मामले के इस दृष्टिकोण में, एक व्यक्ति जो बेचने के लिए समझौते का पक्ष नहीं है और विवाद की विषय वस्तु का संयुक्त मालिक होने का दावा नहीं करता है, वह पक्षकार होने का हकदार नहीं है और ऐसा व्यक्ति न तो आवश्यक है और न ही उचित है।

(पैरा 4)

गुरदेव सिंह और एक अन्य बनाम पारस राम और अन्य, 1985 पीएलजे 315।

अतुल शर्मा बनाम गुरविंदर सिंह और अन्य, 1985 आर.एल.आर.

(अति-शासित)

श्री एन. एल. पुथी, एचसीएस, उप न्यायाधीश, प्रथम *श्रेणी, रोहतक* के दिनांक 15 जून, 1985 के आदेश से सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत संशोधन के लिए याचिका, आवेदन को *खारिज कर दिया गया और पक्षकारों को अपनी लागत को पूरा करने के लिए छोड़ दिया गया।*

याचिकाकर्ता की ओर से- एस सी कपूर, अधिवक्ता ।

प्रतिवादी की ओर से- राम रंग, अधिवक्ता ।

<u>निर्णय</u>

माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. कांग

1. क्या बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में संपत्ति के संयुक्त मालिक होने का दावा करने वाला तीसरा व्यक्ति (मुकदमे की विषय-वस्तु) प्रतिवादी के रूप में शामिल होने का हकदार है, इस संशोधन याचिका में उठाया गया एक छोटा लेकिन दिलचस्प सवाल है।

2. इसमें शामिल मुद्दे की प्राचीन कानूनी प्रकृति को देखते हुए, तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है। यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि टेक चंद ने राम टिकाया के खिलाफ महम, तहसील और जिला रोहतक शहर में स्थित संपत्ति संख्या 113/11 डी बी-वी से संबंधित बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया था। कृष्ण लाल, श्रीमती मोहनी देवी, चंद्र भूषण और उषा रानी ने खुद को राम टिकाया प्रतिवादी के पिता जीवन दास की बेटी श्रीमती राम बाई के बेटे और बेटियां होने का दावा करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए कहा गया और जीवन दास ने संयुक्त रूप से 17 अप्रैल, 1962 के कन्वेंस डीड के तहत कस्टोडियन से समान शेयरों में संपत्ति खरीदी थी। जीवन दास की मृत्यु 6 जून, 1977 को हुई थी, जिसमें राम टिकाया (पुत्र) और श्रीमती लक्ष्मी बाई और श्रीमती राम बाई (बेटियां) कानूनी उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी के रूप में उपरोक्त संपत्ति में अपने डेढ़ हिस्से के उत्तराधिकारी के रूप में थे। जीवन दास की मृत्यु के बाद , राम टिकाया 2/3 हिस्से के मालिक बन गए, जबकि श्रीमती राम बाई और श्रीमती लक्ष्मी बाई को 1/6हिस्सा विरासत में मिला। राम टिकाया प्रतिवादी को किसी भी तरह से आवेदकों के हिस्से को बेचने या स्थानांतरित करने या उनकी ओर से बिक्री के किसी भी समझौते में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था और इसलिए, आवेदकों के हिस्से की सीमा तक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं था। टेक चंद वादी ने स्वाभाविक रूप से मुकदमे में इस घुसपैठ का विरोध किया और आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आवेदकों को पक्षकार बनाए जाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि राम टिकाया प्रतिवादी विवाद में संपत्ति का एकमात्र मालिक था। राम टिकाया प्रतिवादी के कहने पर कार्यवाही में देरी के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से आवेदन दायर किया गया था। प्रतिवादी राम टिकाया की कथित बहनों और आवेदकों के खिलाफ कोई

राहत का दावा नहीं किया गया था , जो आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं थे। ट्रायल जज ने कहा कि राम टिकाया प्रतिवादी ने बेचने के लिए समझौते के निष्पादन से इनकार नहीं किया था। यह उनके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में निष्पादित किया गया था और दस्तावेज से यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि श्रीमती लक्ष्मी बाई या श्रीमती राम बाई को मुकदमे की विषय-वस्तु में कोई दिलचस्पी थी। श्रीमती लक्ष्मी बाई ने पहले भी इसी तरह का आवेदन दायर किया था, जिसे 18 दिसंबर, 1988 को अस्वीकार कर दिया गया था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेदक आवश्यक पक्ष नहीं थे और आवेदन को खारिज कर दिया। इससे परेशान होकर याचिकाकर्ताओं ने ट्रायल जज के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की।

3. पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सुभाष कपूर ने ***गुरदेव सिंह बनाम परस राम, 1985 पीएलजे 315*** में इस अदालत के एक विद्वान शिंगले न्यायाधीश के एक फैसले को मेरे ध्यान में लाया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई थी, जिसमें उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल करने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने दलील दी थी कि विक्रेता, जो विवाद में संपत्ति को बेचने के लिए सहमत हो गया था, उसका मालिक नहीं था और यह आवेदकों के अनन्य कब्जे में था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार किया कि आवेदक विवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक पक्ष थे। यदि उन्हें पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा इस मुद्दे को निर्धारित किए बिना डिक्री किया गया था कि क्या विक्रेता के पास विवाद में भूखंड का स्वामित्व है, तो निष्पादन के समय या एक अलग मुकदमे में मुकदमेबाजी का एक और दौर होगा और चूंकि मुकदमा प्रारंभिक चरण में था, इसलिए संशोधन याचिकाकर्ताओं को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में लागू करना उचित था ताकि पूरा विवाद समाप्त हो जाए और एक ही समय में निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, इससे पहले मैं अकेले बैठा था, मुख्य रूप से **पन्ना खुशाली और अन्य बनाम *जीवन लाल मथू खटीक, एआईआर 1976 मध्य प्रदेश 148 (एफबी)*** मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले के अनुपात पर खुद को आधारित कर रहा ***था। चांद किशोर बनाम सतीश कुमार, 1984 पीएलजे 127: 1984 आरआरआर 347*** मामले में फैसला सुनाते हुए यह विचार लिया था कि विवाद की विषय-वस्तु का संयुक्त मालिक होने का दावा करने वाला तीसरा व्यक्ति बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में एक पक्ष के रूप में शामिल होने का हकदार नहीं है। इसलिए, इस अधिकार क्षेत्र के भीतर न्यायिक राय में दरार को देखते हुए, मैंने मामले को एक खंडपीठ द्वारा निर्णय के लिए भेज दिया। इस प्रकार डिवीजन बेंच में मामला हमारे समक्ष है।

4. बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक साधारण मुकदमे में, प्रतिवादी के खिलाफ मांगी गई डिक्री निष्पादकों के बीच दर्ज अनुबंध के प्रवर्तन के उद्देश्य से है। बिक्री के लिए समझौते के लिए अजनबियों के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी जाती है और वास्तव में, किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के मुकदमे में राहत का कोई अधिकार नहीं है, जो समझौते का पक्ष नहीं है। मुकदमे में शामिल प्रश्न विवाद में संपत्ति में अजनबियों की किसी भी देनदारियों या अधिकारों से संबंधित नहीं है। ऐसे मामले में, वादी, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री प्राप्त करने की स्थिति में, एक बिक्री विलेख निष्पादित करेगा जो केवल उसके निष्पादकों, अर्थात्, वादी और

प्रतिवादी को बाध्य करेगा और उन व्यक्तियों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा जो समझौते के पक्षकार नहीं हैं। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 19 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि किसी भी पक्ष के खिलाफ अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन लागू किया जा सकता है। इसलिए, इस तरह के मुकदमे में एक व्यक्ति जो बिक्री के लिए समझौते का पक्ष नहीं है, न तो आवश्यक है और न ही उचित पार्टी है। यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि वादी एक मुकदमे में ***डोमिनस लिटस*** है । उसे, जब तक किसी क़ानून के प्रावधानों की आवश्यकता न हो, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ वह दावा नहीं करता है या कोई राहत नहीं मांगता है। मुकदमे के दायरे को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए और मुकदमा अनुबंध के किसी भी पक्ष और अनुबंध के लिए अजनबी के बीच एक शीर्षक मुकदमे में बदल गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 10 आदेश 1 के उप-नियम (2) के प्रावधान, न्यायालय को यह निर्देश देने का अधिकार देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल होना चाहिए था या जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि अदालत को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल सभी सवालों पर निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाया जा सके। महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि मुकदमे में शामिल सवालों को निपटाने के लिए ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक होनी चाहिए। विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में शामिल प्रश्न बिक्री के लिए अनुबंध का निष्पादन, अनुबंध के अपने हिस्से को करने के लिए वादी की तत्परता और इच्छा और अनुबंध को निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी के इनकार या असमर्थता हैं। इन सवालों को सेट करने के लिए अजनबियों की उपस्थिति जो अनुबंध के पक्षकार नहीं हैं, आवश्यक नहीं है, यह उचित भी नहीं है। एक व्यक्ति जो अनुबंध के पक्षों के प्रतिकूल शीर्षक का दावा करता है, वह आवश्यक या उचित पार्टी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी जाती है। ऐसे व्यक्ति के जुड़ने से सूट का दायरा बढ़ जाएगा और इसकी प्रकृति बदल जाएगी और यह एक शीर्षक सूट में बदल जाएगा। यह नियम 10 आदेश 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के उप-नियम (2) का उद्देश्य नहीं है। नियम 10 के प्रावधान ***प्रथम दृष्टया*** सक्षम हैं और उस शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। यह केवल तभी होता है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मुद्दे में मामले के पूर्ण निर्णय के उद्देश्य से, एक पक्ष जिसे नहीं जोड़ा गया है, वह आवश्यक है कि नियम 10 के उप-नियम (2) के प्रावधान आकर्षित होते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब तक जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित किसी पार्टी का विवाद और उसके निर्णय में प्रत्यक्ष हित नहीं है, तब तक शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

5. सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 10 आदेश 1 के उप नियम (2) के दायरे और दायरे को माननीय न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ***बनारसी दास दुर्गा प्रसाद बनाम पन्ना लाल राम रिछपाल ओसवाल, एआईआर 1969 पंजाब और हरियाणा 57*** में (जैसा कि तब उनका लॉर्डशिप था) जिसमें यह आयोजित किया गया था:

> "सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के उप-पैरा (2) के तहत, एक व्यक्ति को केवल दो मामलों में मुकदमे में एक पक्ष के रूप में जोड़ा जा सकता है, यानी जब उसे शामिल होना चाहिए था और इस तरह से शामिल नहीं होना किया गया था, यानी जब वह एक आवश्यक पक्ष है, या, जब उसकी उपस्थिति के बिना मुकदमे में प्रश्नों का

पूरी तरह से निर्णय नहीं किया जा सकता है। किसी अन्य मामले में किसी पक्ष को जोड़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, केवल इसलिए कि इससे किसी तीसरे व्यक्ति को संपार्श्विक मामले के निर्णय की मांग के लिए एक अलग मुकदमे के खर्च और परेशानी से बचाया जा सकेगा, जो कि उस मुकदमे में प्रत्यक्ष और ठोस रूप से मुद्दा नहीं था जिसमें वह घुसपैठ चाहता है। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए प्रतिवादी के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि वह संयोग से फैसले से प्रभावित होगा।

आगे यह भी देखा गया -
"एक नियम के रूप में अदालत को किसी व्यक्ति को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में नहीं जोड़ना चाहिए जब वादी इस तरह के जोड़े का विरोध करता है। कारण यह है कि वादी ***डोमिनस लिटस*** है*।* वह सूट का मास्टर है। उन्हें उन लोगों से लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिनके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहते हैं और जिनके खिलाफ वह किसी राहत का दावा नहीं करते हैं।

यह निष्कर्ष निकाला गया था:

"उप-नियम (2) में 'हो सकता है' शब्द एक विवेक को आयात करता है। उस विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय, अदालतें अपने मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में किसी तीसरे व्यक्ति को जोड़ने से पहले वादी की इच्छाओं को ध्यान में रखेंगी। केवल असाधारण मामलों में, जहां अदालत को लगता है कि पार्टियों के बीच विवाद में मामले को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से तय करने में सक्षम बनाने के लिए नए प्रतिवादी को जोड़ना बिल्कुल आवश्यक है, यह वादी की सहमति के बिना एक व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में जोड़ देगा।

6. ***मनमोहन सिंह बनाम सत नारायण, एआईआर 1971 (पी एंड एच) 400*** में माननीय न्यायमूर्ति सोढ़ी, द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के तहत एक आवेदन को अनुमति देने या अस्वीकार करने में जो देखा जाना चाहिए, वह यह था कि क्या एक नए पक्ष को जोड़ना लंबित मुकदमे में आवश्यक जांच के दायरे के अनुरूप होगा और इस तरह के एक पक्ष की अनुपस्थिति में लंबित मुकदमे में विवाद को पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से निपटाना संभव नहीं होगा, ताकि किसी अन्य मुकदमे से बचा जा सके।

7. मुख्य न्यायाधीश आर एस नरूला ने ***काका सिंह बनाम रोही सिंह और अन्य, एआईआर 1978 (पी एंड एच) 30.*** में उपरोक्त दो निर्णयों में लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की।

8. हालांकि, ***अतुल शर्मा बनाम गुरविंदर सिंह, 1985 आर.एल.आर. 226*** में एक अलग टिप्पणी की गई थी। इस मामले में तथ्यों और कानून की व्याख्या के लिए कुछ हद तक विस्तृत संदर्भ की आवश्यकता है। गुरिंदर सिंह ने उनके और राम सरूप, राम चंद और अन्य के बीच हुए बिक्री समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया। अतुल शर्मा और अन्य ने मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया

कि जो संपत्ति समझौते का विषय थी, वह सह-भाड़े की संपत्ति थी और इस तरह, राम सरूप कानूनी आवश्यकता या संपत्ति के लाभ के अलावा इसे बेचने के लिए सक्षम नहीं थे। ट्रायल जज ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए ***एन.टी. पलानीसामी चेट्टियार - एजेंट वी.डी. सीताराम मुदलियार वी। कोमारा चेट्टियार, एआईआर 1950 मद्रास 91*** और बनारसी दास दुर्गा प्रसाद (सुप्रा) में कुछ टिप्पणियों ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया। आवेदक संशोधन में आए थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने बनारसी दास दुर्गा प्रसाद के मामले (सुप्रा) में फैसले के अनुपात का पालन करने में अपनी असमर्थता दर्ज की। उनका विचार था कि बनारसी दास निश्चित रूप से एक उचित पार्टी थे, अगर एक आवश्यक पार्टी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह मामला बाध्यकारी मिसाल नहीं है, क्योंकि फैसला मामले के अजीबोगरीब तथ्यों के आधार पर दिया गया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि **बाल मुकंद बनाम *कमला वती*** और अन्य, एआईआर 1964 सुप्रीम कोर्ट 1385 में उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की स्पष्ट निंदा के सामने, यह नहीं माना जा सकता है कि बेचने के लिए एक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, सह-प्रस्तावकों को कर्ता द्वारा बिक्री के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने बालमुकंद के मामले (सुप्रा) में निम्नलिखित अंश पर भरोसा किया: -

> "वयस्क सदस्यों ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दावे का विरोध नहीं किया होगा यदि वे संतुष्ट थे कि लेनदेन परिवार के लिए फायदेमंद था। यह संभव था कि जिस भूमि को बेचने का इरादा था, वह वर्तमान मुकदमा स्थापित होने तक मूल्य में बढ़ गई थी और इसलिए परिवार के अन्य सदस्य वादी के दावे का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा, परिवार के वयस्क सदस्यों को यह कहने का अधिकार था कि परिवार की संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रबंधक द्वारा उनसे परामर्श किए बिना परिवार को कथित लाभ के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है या अलग करने के लिए सहमत नहीं हो सकता है। यहां इस तरह के किसी परामर्श का कोई आरोप नहीं था। इन परिस्थितियों में नीचे दिए गए न्यायालय विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे को खारिज करने में सही थे।

उन्होंने कहा कि अब यह नहीं कहा जा सकता है कि सह-समर्थक खुद को एक पार्टी के रूप में शामिल करके केवल अपने या विक्रेता के शीर्षक पर निर्णय चाहता है। इसके बजाय, वह विशेष रूप से सह-भाड़े की संपत्ति के खिलाफ बिक्री के समझौते को लागू करने के वादी के अधिकार का विरोध करना चाहता है और सीताराम मुदलियार के मामले (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात पर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी मानना था कि पन्ना खुशाली के मामले (सुप्रा) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित नियम बाल मुकंद के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने बनारसी दास दुर्गा प्रसाद के मामले (सुप्रा) में दृष्टिकोण का पालन नहीं किया है, क्योंकि उनका विचार था कि यह बाल मुकंद के मामले (सुप्रा) के अनुपात के विपरीत था।-------

9. बाल मुकंद के मामले (सुप्रा) में अंतिम न्यायालय द्वारा कानून की सच्ची व्याख्या की सराहना करने के लिए, इस मामले के तथ्यों का उल्लेख करना फायदेमंद होगा, जो ***बालमुकंद हीरा नंद बनाम पिंडी दास (मृतक) और अन्य, एआईआर 1958 पंजाब 267*** में इस न्यायालय की खंडपीठ

द्वारा उस मामले के निर्णय की रिपोर्ट में विस्तृत उल्लेख पाते है। फैसले के शुरुआती पैराग्राफ में तथ्यों को पेश किया गया है। इसमें लिखा है:-

> अदालत ने कहा, 'बटाला निवासी बालमुकंद ने 12 फरवरी 1947 को बटाला निवासी पिंडी दास, हवेली राम, खेम चंद और सतपाल पुत्रगण निहाल चंद के खिलाफ मौजा फैजपुर (बटाला में शामिल) में स्थित 13 कनाल 1 मरला भूमि के 3/20 हिस्से की बिक्री के अनुबंध (रु. 9,687/- के भुगतान पर, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया था। वादी ने आरोप लगाया कि सभी चार प्रतिवादी सगे भाई थे और एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन किया, जिसमें पिंडी दास प्रतिवादी करकुन और प्रबंधक थे, कि प्रबंधक के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 परिवार की संपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था, कि मुकदमे में संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी। 1.10.1945 को प्रतिवादी संख्या 1 ने परिवार के प्रबंधक के रूप में वादी के साथ विवाद में संपत्ति की बिक्री का लेन-देन 250/- रुपये प्रति मरला की दर से किया और वादी से 100/- रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त की, कि प्रतिवादी को बार-बार वादी से शेष बिक्री राशि प्राप्त करने के लिए कहा गया और प्रतिवादी के संबंध में बिक्री विलेख निष्पादित और पूरा करने के लिए कहा गया। मुकदमे में भूमि अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने में विफल रही थी, कि गणना के अनुसार विचाराधीन भूमि की कीमत 9,787/- रुपये थी, और यह कि 100/- रुपये की अग्रिम राशि के रूप में भुगतान करने के बाद वादी 9,687/8/- रुपये के भुगतान पर अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन का हकदार था।

उपरोक्त तथ्यात्मक कथन से यह स्पष्ट है कि वादी ने दलील दी थी कि सभी चार प्रतिवादी सगे भाई थे और एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन किया था, जिसमें पिंडी दास (प्रतिवादी) कर्ता (प्रबंधक) था और परिवार के प्रबंधक के रूप में वादी के साथ विवाद में संपत्ति की बिक्री का लेनदेन किया था और अग्रिम धन प्राप्त किया था। दलीलों से यह भी स्पष्ट है कि वादी ने कहा कि प्रतिवादी (वे सभी) को वादी से शेष बिक्री धन प्राप्त करने और मुकदमे में भूमि के संबंध में बिक्री विलेख निष्पादित करने और पूरा करने के लिए बार-बार कहे जाने के बावजूद, अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने में विफल रहे थे और वह अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के हकदार थे। वादी का मामला यह था कि हालांकि बेचने का समझौता पिंडी दास प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया गया था, लेकिन यह संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों की ओर से था और सभी सह-समर्थकों को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था और उन सभी के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री मांगी गई थी। इस संदर्भ में शीर्ष अदालत ने बालमुकंद के मामले (सुप्रा) में ऊपर दी गई टिप्पणियां की थीं। हालांकि, इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि बालमुकंद के मामले (सुप्रा) में पक्षों के पक्षकार बनने के संबंध में कोई विवाद नहीं था। सभी सह-अभियोजकों को पहले से ही प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था और उनके खिलाफ अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री मांगी गई थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से सभी बचावों को अपने लिए खुला रखना था। विद्वान न्यायाधीश के संबंध में यह निर्णय, आदेश 1, नियम 10 (2), सिविल प्रक्रिया संहिता के सही दायरे का अर्थ निकालने में मदद नहीं करता है। पन्ना खुशाली के मामले (सुप्रा) में इस मामले की बहुत विस्तार से जांच की गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया:-

> "चाहे बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, जो विक्रेता के खिलाफ एक खरीदार द्वारा स्थापित किया गया है, अनुबंध के लिए एक अजनबी है, जो यह तर्क देता है कि अनुबंधित संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है, जिसका वह सह-मालिक भी है, मुकदमे में हस्तक्षेप करना चाहता है, एक पक्ष के रूप में जुड़ने का हकदार है।

इस विषय से संबंधित विभिन्न प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों पर ध्यान दिया गया और उनका विश्लेषण किया गया और ***रजिया बेगम बनाम अनवर बेगम, एआईआर 1958 सुप्रीम कोर्ट 886*** में निर्णयों के अनुपात के आलोक में; **बनारस बैंक** ***बनाम भगवान दास, 1947 इलाहाबाद 18 (एफ.बी.); प्रेम सुख गुलगुलिया बनाम हबीब उल्लाह, एआईआर 1945 कलकत्ता 355 (डी.बी.)*** और ***कहोतरा मोहन ट्रिबुरा*** बनाम ***मोहम्मद सदिर***, ***एआईआर 1964 त्रिपुरा 16*** के न्यायिक आयुक्त का निर्णय**,** प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया था और यह माना गया था कि आवेदक वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं थे। यह भी माना गया कि प्रतिवादी (विक्रेता) के शीर्षक के प्रतिकूल दावा करने वाले अनुबंध के अजनबियों ने तर्क दिया कि वे अनुबंधित संपत्ति के सह-मालिक हैं, न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्ष हैं और इसलिए, मुकदमे में पक्षकारों के रूप में शामिल होने के हकदार नहीं हैं। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह फैसला सुनाया। ***टी रंगय्या रेड्डी बनाम वीआर सुब्रमण्यम अय्यर, एआईआर 1918 मद्रास 681 (एफबी)*** ने भी यह विचार व्यक्त किया था कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में, उन लोगों को आरोपित करने की अनुमति नहीं है जो अजनबी हैं और जिनके दावे की जांच की जानी है। ***रसिकलाल शंकरलाल सोनी बनाम नटवरलाल शंकरलाल उपाध्याय, आकाशवाणी 1975 गुजरात 178***, प्रतिवादी की बहनें, जिन्होंने बिक्री के लिए समझौते के निष्पादन में उसका साथ नहीं दिया था, को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी, हालांकि उन्होंने दावा किया था कि वे हिंदू कानून के तहत मुकदमा संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार थे और भाई द्वारा दर्ज की गई मुकदमा संपत्ति के संबंध में बिक्री के लिए समझौता उन पर बाध्यकारी नहीं था। हाल ही में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ***साधु बेहरा बनाम कृष्ण चंद्र सुतार***, ***एआईआर 1985 उड़ीसा 93: 2006 (2) आरसीआर (सिविल) 172*** में कहा है कि विक्रेता के खिलाफ क्रेता द्वारा स्थापित बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, अनुबंध के लिए एक अजनबी एक पक्ष के रूप में जोड़े जाने का हकदार नहीं है, भले ही उसने तर्क दिया हो कि अनुबंधित संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है जिसका वह सह-मालिक भी था। ऐसे मामले में, विशेष रूप से जब तीसरे पक्ष को जोड़ने पर मुकदमे में कब्जे के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था, तो यह मुकदमे के दायरे को बढ़ाएगा और मुकदमे को शीर्षक के लिए मुकदमा बना दिया जाएगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए तीसरे पक्ष में शामिल होना उचित होगा क्योंकि केवल इस आधार पर, एक पार्टी जो अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आती है जो दृढ़ संकल्प के लिए प्रश्न को नियंत्रित करती है कि कौन एक उचित पार्टी है, उसे मुकदमे में उचित पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। जब वादी शीर्षक लेने के लिए तैयार है, जो उसके विक्रेता के पास था, और मुकदमा संपत्ति के कब्जे के लिए कोई राहत का दावा नहीं किया गया था और न ही आवेदकों के खिलाफ किसी राहत का दावा किया गया था, तो बाद में उसे एक पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सुभाष कपूर ने हमें ***शिवशंकरप्पा महादेवप्पा पराकानहट्टी बनाम शिवप्पा परप्पा कुपति***, ***एआईआर 1943 बॉम्बे 27***, बंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया, जहां यह कहा गया था कि कुछ भूमि की बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, ऐसे व्यक्ति जो विक्रेता पर संपत्ति का प्रतिकूल दावा करते हैं और जो संपत्ति के कब्जे में हैं और जिनके कब्जे से वादी के कब्जे के दावे को विफल करने की संभावना है, उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जा सकता है। मामले की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उस मुकदमे में वादी ने न केवल विक्रेता, जिसने वादी को संपत्ति बेचने के लिए अनुबंध किया था, को एक पक्ष-प्रतिवादी बनाया था, बल्कि उसने प्रतिवादी 2 से 20, जो अनुबंध के लिए अजनबी थे, को भी पक्षकार बनाया था क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 संपत्ति के एक हिस्से में रुचि रखता था और अन्य प्रतिवादी उसके वास्तविक कब्जे में थे। जब प्रतिवादी 2 से 20 के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया था, तो उन्होंने अपील में तर्क दिया कि उनके खिलाफ कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती क्योंकि वे विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे के लिए आवश्यक पक्ष नहीं थे। इस दलील को खारिज कर दिया गया था और इसी संदर्भ में उपरोक्त टिप्पणियां की गई थीं।

11. श्री कपूर ने ***खाजा अब्दुल खादर बनाम महबूब साहब***, ***एआईआर 1979 आंध्र प्रदेश 152***, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह कहा गया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 (2) में प्रयुक्त वाद में शामिल सभी प्रश्नों का समाधान' शब्द की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए और मुकदमे के पक्षकारों और तीसरे पक्ष के लिए समान प्रश्नों का निर्णय ऐसे तीसरे पक्ष को पक्षकार बनाकर किया जा सकता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह मामला विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे से संबंधित नहीं था। यह जमीन को बेदखल करने और कब्जे के लिए एक मुकदमा था। इसलिए यह हमारे सामने मौजूद मुद्दे पर निर्णय लेने में सहायक नहीं है।

12. ***गुरदेव सिंह बनाम परस राम, 1985 पीएलजे 315: 1986 आरआरआर 568*** में निर्णय की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इस मामले को सिद्धांत या मिसाल के संदर्भ में किसी भी विस्तार से विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 10 के उप-नियम (2), आदेश 1 और विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों पर विचार और विश्लेषण नहीं किया गया था।

13. परिणाम में हमारा विचार है कि देश में न्यायिक राय की प्रधानता इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, एक व्यक्ति जो बेचने के लिए समझौते का पक्षकार नहीं है, और मुकदमे की विषय-वस्तु का संयुक्त मालिक होने का दावा करता है, प्रतिवादी के रूप में आरोपित होने का हकदार नहीं है। वह न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्ष हैं और हम इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं और दहलीज पर उठाए गए प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। हम आगे मानते हैं कि ***गुरदेव सिंह बनाम पारस राम,*** 1985 पीएलजे 315 और ***अतुल शर्मा बनाम गुरविंदर सिंह, 1985 आरएलआर 226*** में दिए गए फैसले सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं और खारिज किए जाते हैं। कोई कीमत नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा